

भारत राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 8, 1971/पौष 18, 1892

No. 19] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 8, 1971/PAUSA 18, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह भला संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January 1971

S.O. 220.—In exercise of the powers conferred by section 109 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), the Central Government, being of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby makes the following Order, namely:—

That a person referred to in clause (c) of sub-section (4) of section 39 of the said Act who makes an application in pursuance of the said clause for the grant of a certificate shall be exempted from the operation of the time limit specified in the proviso to the said clause (c) if he repays the loan, within a period of three years from the date of the grant of such certificate, in such instalments as the authority by which the loan was granted may specify in this behalf.

[No. F. 15/32/70-GC. II.]

JASJIT SINGH, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व और बीमा विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी 1971

का० प्रा० 220.—स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, इस राय पर पहुँचने के पश्चात् कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति को, जो उक्त खण्ड के अनुसरण में प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए आवेदन देता है उक्त खण्ड (ग) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट समय-परिसीमा के प्रवर्तन से छूट दे दी जाएगी यदि वह उधार को, ऐसे प्रमाणपत्र दिए जाने की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर, ऐसी किस्तों में प्रतिसंदत्त कर देता है, जो उधार मंजूर करने वाले प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं।

[सं० फा० 15/32/70-जी० सी० II.]

जसजीत सिंह, संयुक्त सचिव।